साप्ताहिक

केशरी दर्पण

RNI. No. UPHIN/2010/36806

w w w.kesharidarpan.com

शख्सियत/प्रमुखता

www.kesharidarpan.com

सम्पादकः सुभाष चन्द

मो. 9837749557

सच्चाई सामने होगी

वर्षः16, अंकः 19 E-mail: subhashchand4@gmail.com बागपत, सोमवार, 18 से 24 मई 2026 (पृष्ठः4) मूल्य 3 रुपया.

निर्यात में उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका हिस्सेदारी 35 प्रतिशत से ज्यादा रही

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल कुल निर्यात में उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत से ज्यादा रही। निर्यात विविधता का फायदा भारत को मिलने लगा है। 2025-25 में इन देशों को 441.78 अरब डालर का वस्तु निर्यात किया गया। वैश्विक व्यापार में व्यवधान के बावजूद भारत द्वारा निर्यात विविधता और नए बाजार तलाशने की कवायद का ही नतीजा रहा कि अप्रैल में निर्यात 13 प्रतिशत बढ़कर 43.56 अरब डालर रहा।

पूर्वी अफ्रीका को निर्यात 13.7 प्रतिशत बढ़कर 12.6 अरब डालर हो गया। उत्तरी अफ्रीका को निर्यात 14.8 प्रतिशत बढ़कर आठ अरब डालर हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि 2025-26 में भारत का निर्यात बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को दिखाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो कुल निर्यात में उत्तरी अमेरिका का दबदबा बना हुआ है और पिछले साल इस क्षेत्र को निर्यात 97.7 अरब डालर रहा। यह कुल निर्यात का 22.1 प्रतिशत है। हालांकि, निर्यात में वृद्धि की बात करें तो यह साल-दर-साल मात्र 1.3 प्रतिशत रही।

सबसे ज्यादा तेजी उत्तर-पूर्व एशिया क्षेत्र में रही। इस क्षेत्र में निर्यात 21.6 प्रतिशत बढ़कर 41.6 अरब डालर हो गया और इससे भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गई।

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुनार और स्वर्णकार समाज की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कहा कि प्रदेश में दिनदहाड़े सुनारों के साथ हो रही लूट की घटनाओं की समस्या अभी सुलझी भी नहीं थी। अब 'सोनाबंदी' और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी ढाई गुणा बढ़ाने जैसे फैसलों से कारोबार प्रभावित हो रहा है।

बड़ी कंपनियों के बाजार में आने से छोटे सुनार पहले से ही प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। डर है कि लाखों छोटे सुनारों का कारोबार बंद हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियां बाद में छोटे-बड़े शहरों में अपने शोरूम खोलकर मनमाने दामों पर गहने बेचेंगी।

राष्ट्रपति एक समारोह में अल्गोजा वादक तगा राम और पैरा-एथलीट प्रवीण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित करेंगी

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक समारोह में अल्गोजा वादक तगा राम और पैरा-एथलीट प्रवीण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। अल्गोजा नामक पारंपरिक वाद्ययंत्र को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए तगा राम पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।

तगा राम ने थार रेगिस्तान के पारंपरिक लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार में उनके असाधारण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले विश्व के नंबर 1 पैरा हाई जंपर पैरालिंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को भी उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मामले के निस्तारण की मांग की है। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार याची लाभ का प्रस्ताव पेश करे, ताकि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ में होगी। चार फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों के संबंध में सरकार क्या सोच रही है।

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने जा रही

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने जा रही है। प्रस्तावित आयोग पंचायतों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति, प्रतिनिधित्व और जनसंख्या अनुपात का अध्ययन करेगा।

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। सरकार यह पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप कराना चाहती है, ताकि भविष्य में आरक्षण व्यवस्था न्यायिक चुनौती में टिक सके। आयोग पंचायतवार पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करेगा और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर सरकार को अपनी अनुशंसा देगा। सूत्रों के अनुसार आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे, जिनमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में रहेगा तथा उसका कार्यकाल छह माह का होगा।

आयोग को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का लक्ष्य दिया जाएगा। यह आयोग उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अलग होगा और इसका कार्यक्षेत्र केवल ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े अध्ययन तक सीमित रहेगा। यह आयोग स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, राजनीतिक और प्रतिनिधित्व संबंधी स्थिति का अध्ययन करता है। आयोग यह जांच करता है कि किस जिले, पंचायत में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना है और वहां आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता कितनी है।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के पत्रकार बने

भारत के किसी भी जनपद, तहसील या थाना क्षेत्र में केशरी दर्पण समाचार पत्र के पत्रकार बनने के लिए संपर्क करें। आप केशरी दर्पण समाचार पत्र की वेबसाइट से भी के माध्यम से भी पत्रकार बन सकते हैं। समाचार पत्र की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें लॉगिन करें आप स्वयं केसरी दर्पण समाचार पत्र की वेबसाइट पर समाचार फोटो आदि भी अपलोड कर सकते हैं। सोनीपत जनपद में श्रीमती अंजू देवी पत्नि श्री कृष्ण पाल, सोनीपत मो. 9416957607

निवेदक-सुभाष चंद, संपादक, केशरी दर्पण (हिंदी साप्ताहिक) 9837749557

w w w.kesharidarpan.com

अधिवक्ताओं की लाठीचार्ज के विरोध तीन दिन के पूर्ण बहिष्कार और सामूहिक अवकाश की घोषणा

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर चैंबर तोड़े जाने के दौरान अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने 18 से 20 मई तक तीन दिन के पूर्ण बहिष्कार और सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है।

सेंट्रल बार एसोसिएशन की आकस्मिक आम सभा अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल की अध्यक्षता में हुई, जबकि संचालन महामंत्री अवनीश कुमार दीक्षित ने किया। सभा में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक में पुलिस प्रशासन पर निहत्थे वकीलों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया। कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था संभालने के बजाय वकीलों पर बल प्रयोग कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है।

महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बताया कि आमसभा में पांच प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय लिया गया कि 18 से 20 मई तक लखनऊ जनपद के सभी न्यायालयों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। इसके बाद 20 मई को दोपहर दो बजे फिर से आमसभा बुलाई गई है, जिसमें जिले की सभी बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।

भाजपा-कांग्रेस के बीच नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर सियासी टकराव

सपना कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। रविवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि 22 लाख मेहनती छात्रों के भविष्य से ऊपर क्षुद्र राजनीति को तरजीह दी है। कहा कि विपक्ष छात्रों की चिंता करने के बजाय इस मुद्दे पर राजनीतिक अवसरवाद कर रहा है।

राहुल गांधी ने नीट-यूजी पेपर लीक विवाद, सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया और तीन-भाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर छात्रों को विफल करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए माफी मांगने की मांग की थी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस रचनात्मक सुझाव देने के बजाय अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर छात्रों के भविष्य के बजाय तुच्छ राजनीति को चुना है। एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की रणनीति छात्रों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना है। मोदी सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई की है और जांच एजेंसियों ने कथित मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।कई राज्यों में चल रही कार्रवाई यह साबित करती है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। यह कोई लीपापोती नहीं है, न ही चुप्पी। यह निर्णायक और संस्थागत कार्रवाई है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार मेहनती और ईमानदार छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने छह नये व दो प्रोन्नत राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह नये और दो प्रोन्नत राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। मनोज पांडेय को खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया है। सरकार की मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना संचालित होती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर वापस सरकार में मंत्री के रूप में लौटे भूपेन्द्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। एक जिला, एक उत्पाद योजना इसी महकमे से संचालित होती है।

राज्यमंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में प्रोन्नत अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री से प्रोन्नत होकर स्वतंत्र प्रभार पाने वाले सोमेन्द्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग का दायित्व दिया गया है। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री सुरेन्द्र दलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान का कद कम हो गया है। उनसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग वापस ले लिया गया है। अब उनके पास खादी, रेशम, हथकरघा उद्योग ही रह गया है।

सरकारी स्कूलों में बच्चों को खेल, कंप्यूटर व गतिविधियों से जोड़ने, अंशकालिक अनुदेशकों के चेहरों पर खुशी

नितिन कुमार सिंह, 17.5, बागपत। गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खेल, कला, कंप्यूटर और गतिविधियों से जोड़ने वाले अंशकालिक अनुदेशकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा के बाद बागपत में भी उत्साह का माहौल रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रत्येक विकास खंड से चयनित एक-एक अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया और उन्हें चेक वितरित किए गए। वहीं जिलेभर में कुल 33 अनुदेशक कार्यरत है।

लखनऊ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी समारोह में दिखाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर के 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा की। अनुदेशकों एवं उनके परिवारजनों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की भी घोषणा की।

राज्यमंत्री केपी मलिक जी ने कहा कि गांव के बच्चों को नई दिशा देने में अनुदेशकों की बड़ी भूमिका है। खेल, कला, कार्य शिक्षा और कंप्यूटर जैसी गतिविधियां बच्चों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास को मजबूत करती हैं।

विधायक डॉ अजय कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा वातावरण मिले, इसके लिए अब मानदेय बढ़ने से अनुदेशकों का मनोबल और मजबूत होगा, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों के वातावरण पर दिखाई देगा।

जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षक और अनुदेशक दोनों अहम कड़ी हैं। जब शिक्षा से जुड़े लोगों को सम्मान और आर्थिक संबल मिलता है तो उसका सकारात्मक असर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है।

कार्यक्रम में विकसित उत्तर प्रदेश और शिक्षित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित विशेष फिल्म का भी प्रसारण किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं, स्कूलों में बढ़ती सुविधाओं व शिक्षकों-अनुदेशकों के योगदान को दिखाया गया। अंशकालिक अनुदेशकों ने बताया कि पहले मानदेय में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ स्कूल की गतिविधियों को संभालना चुनौतीपूर्ण होता था। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता चौधरी सहित विभिन्न अधिकारीगण मौजूद रहे।

बागपत पुलिस ने असलहा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया

नितिन कुमार सिंह, 17.5, बागपत। पुलिस ने असलहा बनाने वाले गिरोह, दो भाइयों समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना दो भाइयों का पिता भागने में कामयाब हो गया। ठिकाने से असलहे का जखीरा बरामद हुआ है।

शनिवार को एसपी सूरज कुमार राय ने रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में बताया कि बड़ौत कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से शुक्रवार रात बड़ौत में बावली रोड नहर पटरी स्थित खंडहर में छापामारी की, जहां पर असलहा का निर्माण किया जा रहा था। आरोपित झोलाछाप सलीम पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम करनावल, मेरठ हाल निवासी पांची, फरमान व शोएब पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम पांची को गिरफ्तार किया।

मृत पिता के नाम पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन निकालने पर थाना गन्नौर में केस दर्ज

राजवीर सिंह, सोनीपत। गांव पट्टी ब्राह्मण निवासी युवक के खिलाफ अपने मृत पिता के नाम पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन निकालने के आरोप में थाना गन्नौर में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पिता की मौत के बाद भी कई वर्षों तक एटीएम के माध्यम से पेंशन राशि निकाली।

सोनीपत जिला समाज कल्याण अधिकारी की शिकायत के अनुसार बुजुर्ग की मृत्यु 10 जनवरी 2017 को हो चुकी थी, लेकिन फरवरी 2017 से जुलाई 2024 तक उनके खाते से पेंशन निकाली गई। जांच में करीब दो लाख तीन हजार 500 रुपये की राशि गलत तरीके से निकाले जाने की बात सामने आई।

नोटिस भेजने के बावजूद आरोपित ने केवल 9787 रुपये जमा करवाए, एक लाख 93 हजार 713 रुपये की राशि अब भी बकाया है। संबंधित बैंक से भी रिकवरी को लेकर पत्राचार किया था। जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी प्रकरण उठा था।

आरोपित के नाम कोई संपत्ति दर्ज नहीं मिली। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना गन्नौर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

केंद्रीय मंत्री के बेटे को पोक्सो मामले में जेल भेज दिया

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। शनिवार रात गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को पोक्सो मामले में जेल भेज दिया गया है। उसे मजिस्ट्रेट ने 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भगीरथ के वकील करुणा सागर ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी का झूठा दावा कर रही है। नाबालिग लड़की की मां की शिकायत के आधार पर बीएनएस और यौन उत्पीड़न से नाबालिगों के बचाव के लिए बने कानून पोक्सो के तहत भगीरथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भगीरथ ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

भगीरथ ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि लड़की और उसके माता-पिता ने उस पर शादी करने का दबाव डाला। जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो लड़की के माता-पिता ने पैसे मांगे और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो झूठी शिकायत दर्ज करा देंगे।

कोशिश करो तैयार रहो सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध

प्रधान कार्यालयः निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101

Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 7906984078

संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें।

स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।

(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

राहुल गाँधी जी या राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बना कर देखलो शायद ये वैश्विक संकट टल जाये कहा तो मिली सुभाष कश्यप धमकी

आदरणीय मोदी जी के आवाहन पर सुभाष चंद कश्यप ने खेकड़ा बाजार पुलिस चौकी से खेकड़ा तहशील तक बिना स्टार्ट किये अपनी बाइक ले जाकर, पैट्रॉल बचाने का संदेश दिया था।

नितिन कुमार सिंह, बागपत/खेकड़ा। सुभाष चंद कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी व वर्ष 2029 संभावित प्रत्याशी बागपत लोकसभा ने बताया कि 16 मई को जब वह बागपत कलेक्ट्रट में जिलाधिकारी को जनता की भलाई के लिए ज्ञापन देकर वापस खेकड़ा घर आ रहे थे तो उनके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आयी। जिसने अपना नाम अमित बताया।

कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा के साथ धमकी देते हुए कहा कि मोदी जी से स्तीफा मांगने वाला तू कौन होता है। जैसा चल रहा है चलने दो। देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं तुझे क्या दिक्कत है? भविष्य में दुबारा मोदी जी के विरुद्ध कोई नौटंकी की तो तुझे नेता बना देंगे। जिसकी सुचना थाना बागपत, थाना खेकड़ा को लिखित में और पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत को व्हाट्सप्प पर दे खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

बतादे कि 14 मई को आदरणीय मोदी जी के आवाहन पर कि वैष्विक संकट टालने के लिए पैट्रॉल गैस आदि बचाओ सोना एक साल तक मत खरीदो आदि आवाहन को लेकर सुभाष चंद कश्यप ने खेकड़ा बाजार पुलिस चौकी से खेकड़ा तहशील तक बिना स्टार्ट किये अपनी बाइक ले जाकर, पैट्रॉल बचाने का संदेश दिया था।

सुभाष चंद कश्यप के कहा कि देश ने थाली, ताली बजाई, मोबाइल की टार्च जलाई, हवन किये, नमाज पढ़ी, प्रार्थना की, जहाज के नीचे नींबू भी तोडा लेकिन ये वैश्विक संकट नहीं टल रहा।

सुभाष चंद कश्यप के कहा कि देश बचाने के लिए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की जरुरत है। एक बार आदरणीय राहुल गाँधी जी या आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एक बार प्रधानमंत्री बना कर देखलो शायद ये वैश्विक संकट टल जाये।

एसडीएम ज्योति शर्मा के नेतृत्व में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन

नितिन कुमार सिंह, 15.5, बागपत। जनपद बागपत के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा में एसडीएम बागपत ज्योति शर्मा एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सरूचि शर्मा के नेतृत्व में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया।

कैंप के दौरान कुल 53 बच्चियों का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उपस्थित अभिभावकों को एचपीवी वैक्सीन के महत्व, सर्वाइकल कैंसर से बचाव एवं नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया तथा अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य विभाग जनपद में निरंतर जागरूकता अभियान चलाकर पात्र बालिकाओं तक टीकाकरण सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएससी अधीक्षक बागपत डॉक्टर विभास राजपूत एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भाजपा ने गरीबो को हमेशा धोखा दिया, गरीबो के आरक्षण में दबंगो को शामिल कर गरीबो का पिछले 26 वर्षो से मार दिया, आओ बागपत लोकसभा को भाजपा मुक्त करे

बागपत लोकसभा की जनता जनार्दन आशीर्वाद दे तो एक बार फिर 2029 में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा

निवेदक-

सुभाष चंद कश्यप

पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, 7906984078

पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 जनपद बागपत-2015

राष्ट्रीय महासचिव श्रीराम बाजपेई स्काउट गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया

पता- कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत उत्तर प्रदेश -250101

सम्पादकीय.....

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा रही

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ा कर 38 करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अध्यादेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भारत के प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश हैं। जारी अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआइ सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है।

1950 में जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था तब सीजेआइ को मिला कर कुल आठ न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या उस समय बढ़ी है जब सर्वोच्च अदालत में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्याय को गति देने और लंबित मामलों के जल्दी निपटारे के उद्देश्य से गत पांच मही को सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों को बढ़ाने की मंजूरी दी थी।

पहली बार 1956 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिनियम पारित किया गया जिसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा कर 10 कर दी गई। इसमें सीजेआइ शामिल नहीं थे। इसके बाद 2008 में यह 30 हो गई। 2019 में संख्या 30 से बढ़ा कर 33 कर दी गई जिसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं थे। चीफ जस्टिस को मिला कर 34 न्यायाधीश हो गए थे। और अब चार और न्यायाधीश बढ़ाए गए हैं। लोग दबी जबान कहते नजर आये कि देश पर लगातार किसी न किसी तरह बोझ बढ़ाया जा रहा है ।

कांग्रेस खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करती नजर आई

अंजू देवी, सोनीपत। संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के बूथ-वार आंकड़ों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने जिले के अधिकांश वार्डों में एकतरफा बढ़त हासिल करते हुए कांग्रेस को कड़ी शिकस्त दी है। कुल 22 वार्डों के 264 बूथों के परिणाम बताते हैं कि जहां भाजपा ने शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कई क्षेत्रों में खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करती नजर आई।

कांग्रेस पार्टी जिले के 8 वार्डों में पूरी तरह बेअसर साबित हुई। इन सभी वार्डों में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए शत-प्रतिशत बूथों पर जीत हासिल की। वार्ड 15 और 18 में भी कांग्रेस की स्थिति बेहद नाजुक रही।

जहां एक ओर भाजपा ने जिले के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया, वहीं वार्ड संख्या 19 ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इस वार्ड के सभी 7 बूथों पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को शून्य पर समेट दिया।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग

संसद से कानून पारित कर नयी विधायी टेस्टिंग अथॉरिटी बनाने से संस्था के अध्यक्ष और उसके सदस्य कानून द्वारा तय किये जाएंगे

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने नीट यूजी 2026 में प्रणालीगत विफलता का आरोप लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग की है।

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने याचिका में कहा कि संवैधानिक और संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा पारित कानून के जरिए एक नयी वैधानिक टेस्टिंग अथॉरिटी गठित की जाए। इस नये गठित निकाय के पास परिभाषित कानूनी अधिकार, पारदर्शिता के मानक और विधायिका के प्रति सीधी जवाबदेही होनी चाहिए।

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने वकील रितु रेनीवाल के जरिए दाखिल की गई याचिका में कहा है कि संसद से कानून पारित कर नयी विधायी टेस्टिंग अथॉरिटी बनाने से संस्था के अध्यक्ष और उसके सदस्य कानून द्वारा तय किये जाएंगे, जिससे यह संस्था सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी।

शुरू से अंत तक सीएजी ऑडिट अनिवार्य करने से वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पेपर लीक होने पर सख्त सजा और छात्रों के लिए अनिवार्य शिकायत तंत्र होने से कानूनी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होंगे।

अलीशा मलिक ने सीबीएसई इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विश्वकर्मा समाज का मान बढ़ाया

नितिन कुमार सिंह, बागपत। बड़ौत क़स्बा के बिनोली रोड निवासी देवेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि उनकी बेटी अलीशा मलिक ने सीबीएसई इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विश्वकर्मा समाज का मान बढ़ाया।

यह उपलब्धि न केवल अलीशा के अथक परिश्रम लगन और समर्पण का परिणाम है बल्कि यह उसके मार्गदर्शन, विद्वान शिक्षकों एवं अभिभावक को कैसे सहयोग संस्कार और प्रेरणा का भी प्रतिफल है। अलीशा ने यह है सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प अनुशासन और सकारात्मक सोच से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अलीशा मलिक की उपलब्धि पर सामाजिक नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रशंसा की है।

केशरी दर्पण में समाचार/विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु संपर्क करे,
संपादक- सुभाष चंद
9837749557

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।
www.kesharidarpan.com
पर रजिस्टर/लॉगिन करे।
KD www.kesharidarpan.com
सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

12वीं के परीक्षा परिणामों के बाद छात्रों और अभिभावकों के चिंताओं और असमंजस की स्थिति

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच बढ़ी चिंताओं और असमंजस की स्थिति के मद्देनजर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। इसने स्पष्ट किया है कि नई डिजिटल आन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी नई मूल्यांकन पद्धति को लेकर फैली घबराहट पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि छात्रों का हित और मानसिक सुकून उसके लिए सर्वोपरि है। इसने कहा कि ओएसएम को छात्रों की सहूलियत और निष्पक्षता के लिए ही लागू किया गया है।

अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई इस व्यवस्था से मूल्यांकन में एकरूपता और पारदर्शिता आती है। एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस बार कुल 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया गया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मार्किंग की वजह से पास प्रतिशत में गिरावट आने की आशंकाएं निराधार हैं।

इस साल 12वीं का पास प्रतिशत पिछले साल के 88 प्रतिशत से घटकर 85 प्रतिशत रहा है, लेकिन इसका तकनीक से कोई

प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर की अनिवार्यता समाप्त के बाद बदला जा रहा

गीता, सीतापुर। प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद जिलों और जोन में इनको बदला जा रहा है। प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर के लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

सीतापुर जोन में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। जनता के व्यापक विरोध और मीटर में तकनीकी समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को वापस ले लिया है और इन्हें पोस्टपेड मोड में स्थानांतरित कर दिया है।

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के प्रयोग के दौरान अचानक बिजली कटने के साथ बिलिंग में भारी गड़बड़ी और रिचार्ज की समस्या से परेशान होकर उपभोक्ताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। इसके बाद सरकार ने सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदल दिया गया है।

नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्याओं के निवारण के लिए विभाग पुराने 2ल स्मार्ट मीटरों को 4ल स्पीड वाले मीटरों में अपग्रेड करने का काम कर रहा है, ताकि सेवाएं निर्बाध चल सकें। पोस्टपेड व्यवस्था के तहत आपको बार-बार अग्रिम रिचार्ज करने की झंझट से मुक्ति दी गई है।

अब पूरे महीने की वास्तविक खपत के आधार पर बिल आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में भी चल रहे हैं या जो रिचार्ज कर रहे हैं, उनके लिए रात्रि में बैलेंस खत्म होने पर बिजली न कटने और बिल में दो प्रतिशत तक की छूट जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से सीतापुर जोन के 2,00,133 उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट विद्युत मीटर को पोस्टपेड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पोस्टपेड में मीटर परिवर्तित होने के बाद उपभोक्ताओं को मई का बिल अब जून में मिलेगा। मुख्य अभियंता आरके सिंह ने उपभोक्ताओं से अब हर माह का बकाया बिल जमा करने के लिए अपील भी की है। सीतापुर जोन में लखीमपुर व हरदोई जिले भी आते हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते

विशाल कश्यप, नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की मानें तो अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं। आप कैसे राशन कार्ड बनवा सकते हैं? सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है। इसके बाद आपको यहां पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भरना है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन मेन्यू पर जाना है। फिर पेंडिंग वाले सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है।

जो लोग ए से ई कैटेगरी की कॉलोनियों जमीन या मकान के मालिक हैं। जो लोग करदाता हैं। जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है। जिन लोगों का बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट से अधिक है आदि।

अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप नए राशन कार्ड के लिए आवदेन कर सकते हैं। आप यहां जान सकते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है और आप चाहते हैं कि आप राशन कार्ड बनवा लें, तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देते हुए लगभग 8 साल बाद नए राशन कार्ड बनवाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करना है। जितने लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़वाने हैं, उन सभी के आधार कार्ड

आधार में पता अगर अलग हैं तो दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड बनेगा यानी वो मुखिया होगी। अगर किसी परिवार में कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो फिर परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी तौर पर परिवार का मुखिया माना जाएगा।

नोटः पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार है, सम्पादक का इनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। आप स्वयं जांच करें। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादकः सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादकः राजवीर सिंह , (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)